

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 162] No. 162| नई विल्ली, सुकवार, भ्रप्रेल 30, 1982/वैशाख 10, 1904 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 1982/VAISAKHA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की आती है जिससे कि यह अलग संकलन के कप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय (औधोगिक विकास विभाग)

आवेश

नई वित्ली, 30 श्रप्रैल, 1982

का अगि 290(अ) ---यन, भारत सरकार के उद्योग महास्य (श्रीग्रोगिक विकास विभाग) के श्रादेण सख्या 293(श्र)/18कक/श्राई० ही० श्रार० ए०/78, दिनाक 1-5-1978, जिसे इसमे, इसके पश्चात् उकत श्रावेण कहा गया है, द्वारा एल्युमिनियम कारणोरेणन श्राफ इंडिया लि०, कलकसा के श्रामनभील के सभीप जे० के० नगर में स्थित श्रीग्रोगिक उपक्रम का प्रबध, उद्योग (विकास श्रीर (विनियमन) श्रीधायनम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक, की उपधारा (1) के श्रधील 30 श्रील, 1979 तक (जिसमे यह दिन भी शामिल है) एक वर्ष की श्रयधि के लिए प्रहुण किया गया था श्रीर भारत एल्यूमिनियम कपनी लि० को उकत श्रीग्रोगिक उपक्रम का प्रवेध करने के लिए प्राधकृत किया गया

िष्ठीर सन्, भारत सरकार के उद्योग महालय (श्रीदांगिक विकास विभाग) के बादेगो--विनाक 25 श्रील, 1979 के का॰ श्रा॰ 224(श्र), इनाक 29 श्रप्रैल, 1980 के का॰ श्रा॰ 286(श्र) श्रीर विनांक 31 शक्तूबर 1980 के का॰ श्रा॰ 869(श्र)/18कक/ श्राई॰ डी॰ श्रार॰ ए॰/৪० हारा उक्त श्रादेश की श्रवधि, दिनांक 30 श्रप्रैल, 1981 तक एक वर्ष की श्रविध के लिए बढ़ा दी गई थी।

118 GI/82

ग्रीर यत, भारत सरकार उद्योग महालय (ग्रीदोगिक विकास विभाग) के आदेश दिनोक 30-4-31 के का० आ० 325(अ)/18क्का/आई० डी० आर० ए०/81 द्वारा उक्त ग्रादेश की अवधि विनाक 30 अप्रैल, 1982 तक, जिसमे यह विन भी ग्रामिल है, बढ़ा दी गई थी।

श्रीर यत , केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त श्रीग्रोशिक उपक्रम का 31 जुलाई, 1982 तक 3 महीने की श्रीर श्रवधि के लिए भारत एल्य्मिनियम कंपनी लिए के प्रबंध में बना रहने दिया जाना चाहिए।

श्रव श्रम, केन्द्रीय सरकार श्रीद्योगिक (विकास श्रीर विनियमन) श्रिधिनयम, 1951 (1951 ना 65) की क्षारा 18कक की उपधारा (2) बारा प्रदल शिक्तयों का प्रयोग करने हुए निदेश देती है कि उक्त श्रादेश 31 णुलाई, 1982 तक, जिसमें यह दिन भी शासिल है, तीन सहीने की श्रीर श्रथिष के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा॰ स॰ 4(1)/80-सी॰ य॰ सी॰]

MINISTRY OF INDUSTRY (Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 30th April, 1982

S.O. 290(E)—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 293(E) 18AA | IDRA | 78, dated

1st May, 1978, hereinafter referred to as the said Order, the management of the industrial undertaking located at Jaykaynagar near Asansol belonging to the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta, was taken over under sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), for a period of one year upto and inclusive of the 30th April 1979, and the Bharat Aluminium Company Limited was authorised to take over the management of the said industrial undertakings;

And, whereas by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 224(E), dated the 25th April 1979, No. S.O. 286(E), dated the 29th April 1980, and No. S.O. 869(E)|18AA|IDRA|80, dated the 31st October 1980, the duration of the sald order was extended for a period upto the 30th April 1981;

And, whereas by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 325(E)18AA|IDRA|81, dated the 30th April 1981, the duration of the said Order was extended upto and inclusive of the 30th April 1982;

And, whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said idustrial undertaking should continue under the management of the Bharat Aluminium Company Limited for a further period of three months upto the 31st July 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation)) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period of three months upto and inclusive of the 31st July 1982.

[F. No. 4(1)|80CUS]

आवेश

का० आ० 291(अ).—-प्तः, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (भीद्योगिक विकास विद्याग) के दिनाक 2 मई, 1978 के भावेश संख्या का० अ०२(भ्र)/18 एफ० बी०/भाई० डी० भार० ए०/78 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त श्रादेश कहा गया है) हारा केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास भीर धिनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की घारा 18चळ की उपधारा (1) खंड (ख) हारा प्रवत्न शिक्तयों का प्रयोग करने हुए यह बोथणा की थी कि उक्त मादेश के जारी होने की तारील के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसे सभी संविवाभों, संपत्ति के हस्ताक्षरण-पत्नों, करारों, समझौतों, स्थायी भावेशों या भन्य निकातों, जित्ता एक्ष्मिनियम कारणीरेशन भाफ इंडिया निमिटेड, कलकता के भ्रमानसोल के भमीप जे० के० नगर स्थित भौद्योगिक उपक्रम; एक पक्षकार है, या जो उक्त भौद्योगिक उपक्रम एर लागू हो सकते हों, का प्रवर्तन एक वर्ष की भ्रविध के निए निलम्बित रहेंग भीर उक्त सारील के पूर्व उनके भ्रधीन प्रोद्मृत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाचताएं भीर वायित्व एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बत रहेंगे;

भीर यतः, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (भीदाधिक विकास विभाग) के प्रादेशों →िदिनोंक 25 भरैल, 1979 के कु० भा० 225(भू 18क्ब | माई० डी० भार० ए०/79, विनोंक 29 भरैल, 1980 के का०भा० 287(भ)/18च्च | माई० डी० भार० ए०/80, विनोंक 31 भक्तूबर, 1980 के का० भा० 870/18 चच | माई० डी० भार० ए०/80 द्वारा उक्त भादेश की भाष 30 भरैल, 1981 तक की भवधि के लिए भीर बढ़ा दी गई की

भीर यतः, भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (भौधोगिक विकास विभाग) के विनाक 30 भन्नैल, 1981 के कार्ष भाव 326(भ)/18 च ख/भाई० डी॰ भार॰ ए॰/81, विनाक 30 भन्नैल, 1982 तक, जिसमें यह दिन भी शामिल है, बढ़ा दी गई थी।

भीर यतः, केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि उक्त श्रादेश की श्रवधि भीर तीन महीने यानी 31 जुलाई, 1982 तक, जिलमें यह दिन भी णामिल है, बढ़ा देनी चाहिए।

श्रव, श्रतः केट्स सरकार उद्योगु (विकान श्रीर विनियमन) श्रीक्षित्यम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चका की उपधारा (2) के साथ पिटन उपधारा (i) द्वारा प्रदन्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त श्रादेश की अवधि 31 जुलाई, 1982 नक, जिसमें यह दिन भी गामिल है, बढ़ाती है।

[फा॰ मं॰ 4(1)/80-सी॰ यु॰ एस॰] चन्द्र किशोर मोदी, संयुक्त संचिष्ठ

ORDER

S.O. 291(E).—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 302(E)/FBI/IDRA/78, dated the 2nd May 1978, (hereinafter referred to as the said order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurance of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said order to which the industrial undertaking located at Jaykaynagar near Asansol and belonging to the Aluminium Corporation of India Limited, Calcutta, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking, shall remain suspended for a period of one year and that all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for a period of one year;

And, whereas by the orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 225(E).18FB|IDRA|80, dated the 25th April 1979, No. S.O. 287(E)|18FB|IDRA|80, dated the 29th April 1980, No. S.O. 870|18FB|IDRA|80, dated the 31st October 1980, the duration of the said order was extended for a period upto the 30th April 1981.

And, whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 326(E)|18FB|IDRA|81, dated the 30th April 1981, the duration of the said order was extended upto and inclusive of the 30th April 1982;

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said order should be extended for a further period of three months upto and inclusive of the 31st July 1982:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act. 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said order upto and inclusive of the 31st July 1982.

[F. No. 4(1)|80-CUS] C. K. MODI, Jt. Secy.